P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का समीक्षात्मक अध्ययन

सर्पराज रामानन्द सागर
अतिथि सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
टी0 एन0 बी0 महाविद्यालय,
भागलपुर, बिहार, भारत

सारांश

भारत एक विकासशील देश होने के साथ ही विश्व की दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है। यहां गरीबी व बेरोजगारी की समस्या स्वतंत्रता पूर्व से ही रही है। हालांकि सरकार द्वारा गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु विभिन्न योजनाओं के द्वारा कम करने का प्रयास कर रही है इसमें सफलता भी हाथ लगी है। परंतु पूर्ण रूप से गरीबी व बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। बेरोजगारी व गरीबी दोनों में ही गहरा संबंध है। बेरोजगारी से ही गरीबी उत्पन्न होती है। भारत में गरीबी या बेरोजगारी का मुख्य कारण पूंजी की कमी का होना है। सरकारी विनियोग के माध्यम से उपलब्ध ऋण अनुत्पादक कार्यों में खर्च हो जाता है। बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी भत्ता, मनरेगा, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदि सरकारी योजनाएँ इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। भारत में गरीबी व बेरोजगारी को कम करने के लिए, पूंजी के आभाव के कारण रोजगार या व्यापार न कर पाने वालों के लिए, पूंजी की कमी के कारण अपना उद्योग का विस्तार नहीं कर पाने वालों, नया उद्यम या व्यापार नहीं कर पाने वालों के लिए भारत सरकार ने एक विशेष योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरूआत 8 अप्रैल 2015 को की है। इस योजना से रोजगार को बढ़ावा, गरीब उन्मूलन, व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

मुख्य शब्द : बेरोजगारी, पूंजी, गरीबी, अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

भारत में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय आज भी कृषि ही है। यहां के अधिकांश लोग अपना जीवन–यापन कृषि से ही करते हैं। कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी है। आज के समय में भारत में बेरोजगारी की समस्या विकराल हो रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) ने भारत में 2018 में बेरोजगारी की दर 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि भारत में बेरोजगारी की दर 2017–18 में 6.1 प्रतिशत रही जो पिछले 45 साल में सर्वाधिक है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर 7.5 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 5.3 प्रतिशत रही । वही अखिल भारतीय स्तर पर पुरूषों की बेरोजगारी दर 6.2 प्रतिशत जबकि महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.7 प्रतिशत रही। एक–दो दशकों में सेवा क्षेत्र में हालांकि भारत में अच्छी तादाद में रोजगार बढ़े है। रोजगार के मामले में असंगठित और असुरक्षित रोजगार का बोलवाला है। असंगठित क्षेत्र में 90 प्रतिशत कामगार है। इसके पीछे कृषि क्षेत्र में रोजगार का बढ़ना मुख्य कारण है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत 8 अप्रैल 2015 को की ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, नया उद्याम स्थापित कर सके, अपने उद्यम का विस्तार कर सके, व्यापार कर सके। मुद्रा (MUDRA) यानी माइक्रो युनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड द्वारा उत्पादक कार्यों हेतु ऋण लेने में आसानी होगी। इससे रोजगार के साथ–साथ नये उद्यमी व व्यापारी भी बढेंगें। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति (जो भारत का निवासी है) अपना स्वरोजगार हेतु व्यापार हेतु नया उद्यम स्थापित करने या अपने–अपने उद्योग का विस्तार करने के लिए बिना गारंटर के बैंक से आसानी से लोन प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत तीन प्रकार के लोन होते है–

अध्ययन का उद्देश्य

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभों का अध्ययन करना है।
2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा बेरोजगारी को कम करने का अध्ययन करना है।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का अध्ययन करना है।
4. इस योजना के लिए उपयुक्त सुझाव देना इत्यादि है।

शिशु लोन

इसके अंतर्गत 50,000 रू0 तक का लोन दिया जाता है। यह लोन उन लोगों के लिए है जो अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं।

किशोर लोन

इसके अंतर्गत 50 हजार रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक का लोन दिया जाता है। यह लोन उनलोगों को उपलब्ध होगा जो अपना व्यापार तो शुरू किए है। परंतु सही ढंग से स्थपित नहीं कर सके हैं।

तरूण लोन

इसके अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रूपये तक का लोन देने का प्रावधान है। यह लोन उन लोगों के लिए है जो अपना व्यापार या उद्यम का विस्तार करना चहते है।

इस योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है–

1. इसमें किसी भी तरह के व्यवसाय हेतु लोन मिलता है।
2. इसमें निजी कार्यों हेतु लोन नहीं ले सकते है।
3. यह योजना बेरोजगारी को कम करने व स्वरोजगार को बढ़ाने हेतु चलाया गया है।
4. इसमें तीन प्रकार के शिशु लोन, किशोर लोन व तरूण लोन दिये जाते है।
5. इसमें लोन लेने वालों को किसी भी प्रकार का गारंटर नहीं देना होता है।
6. इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति (जो भारतीय है) ले सकता है
7. छोटे व सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से कर्ज दिलाने हेतु प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए उपर्युक्त ढॉचा तैयार करना।
8. इस योजना के द्वारा जीडीपी में उच्चतर वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
9. इसमें ब्याज की दर को 12 प्रतिशत रखा गया है।
10. सूक्ष्म उद्योगों के लिए कम लागत वाला वित्त उपलब्ध

योजना की प्रगति (अब तक)

इस योजना 1,37,449.29 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में रूपये के लोन स्वीकृत किये गये जिसमें से 1,32,954.7करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1,75,312.13 करोंड़ रूपये व वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2,46,437.40 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 3,11,811.38 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया। (स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण मुद्रा योजना 2016–17, 17–18) इस योजना की सहायता देश के लगभग 200 संस्थाएं कर रही है। 2017–18 में लक्ष्य से अधिक का वितरण किया गया। इस योजना के प्रावधान के मुताबिक 75 प्रतिशत लोन महिलाओं को दिया गया है। वहीं कुल लोन का 50 फीसदी तक के मुद्रा कर्ज अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को दिया गया है।पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 1.12 करोड नौकरियाँ पैदा की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वितरित ऋण (करोड़ रूपये)–

बैंक का नाम	शिशु लोन	किशोर लोन	तरूण लोन	कुल
SBI व सहयोगी बैंक	6113.25	10676.62	1682.12	3361.25
सार्वनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक	4254.94	29298.35	26202.12	59754.41
निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक	34281.22	19775.89	9566.96	63624.7
विदेशी बैंक	0	8.36	22.25	30.61
राज्य सहकारी बैंक	1	0.6	0	1.6
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2651.32	11636.72	2399.44	16687.08
सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएँ	2357.41	0	0	2357.41
NBFC सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएँ	56733.62	2055.06	327.01	59115.7
नन बैंकिग वित्तीय कंपनिया	13281.26	20877.34	12706.48	46865.09
सूक्ष्म वित्तीय बैंक	19977.52	5539.94	4245.45	29762.92
कुल ऋण	139651.55	99868	72291.84	311811.38

(स्रोतः PMMY आर्थिक समीक्षा 2018–19)

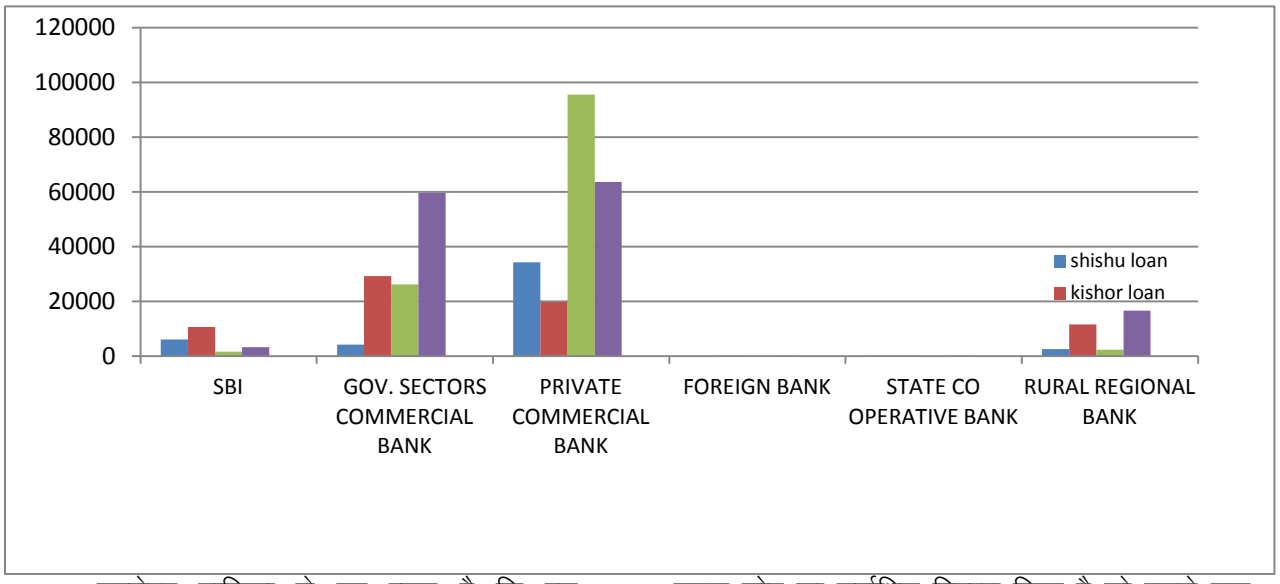

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि इस योजना के तहत कुल वितरित ऋण में शिशु लोन का वितरण सर्वाधिक हुआ है। कुल वितरित ऋण में शिशु लोन का हिस्सा 44.78 प्रतिशत है। वहीं किशोर लोन ब तरूण लोन की हिस्सेदारी क्रमशः 32.02 प्रतिशत व 23.18 प्रतिशत है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि शिशु लोन का सर्वाधिक वितरण NBFC सूक्ष्म वित्तीय संस्था ने किया है जो इसके कुल वितरण ऋण का 96 प्रतिशत है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंको ने किशोर लोन व तरूण लोन का सर्वाधिक वितरण किया है जो इसके कुल वितरण का क्रमशः 49 प्रतिशत व 44 प्रतिशत है। अतः सूक्षम वित्तीय संस्थाएँ शिशु लोन के वितरण में अधिक भागीदारी के कारण नये उद्यमी उत्पन्न हो रहे हैं। सुक्ष्म वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना अन्य बैंकों की अपेक्षा आसान होता है। अतः लोगों ने शिशु लोन के लिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को चुना है।वित्तीय वर्ष 2018–19 में सर्वाधिक लोन वितरित करनेवाले कुछ प्रमुख्य राज्य इस प्रकार है–

राज्य	**करोड़ रूपये में वितरित ऋण**	**प्रतिशत हिस्सेदारी**
तमिलनाडु	33807.87	10.84
कर्नाटक	29345.44	9.41
पश्चिम बंगाल	25892.29	8.30
महाराष्ट्र	25741.99	8.25
बिहार	23068.32	7.3981
उत्तर प्रदेश	24888.92	7.98
राजस्थान	17007.35	5.45
मध्य प्रदेश	16792.33	5.38
उडीसा	15284.62	4.90
आंध्रप्रदेश	10669.25	3.42
कुल ऋण	311811.38	100

(**स्रोतः** PMMY समीक्षा 2018–19)

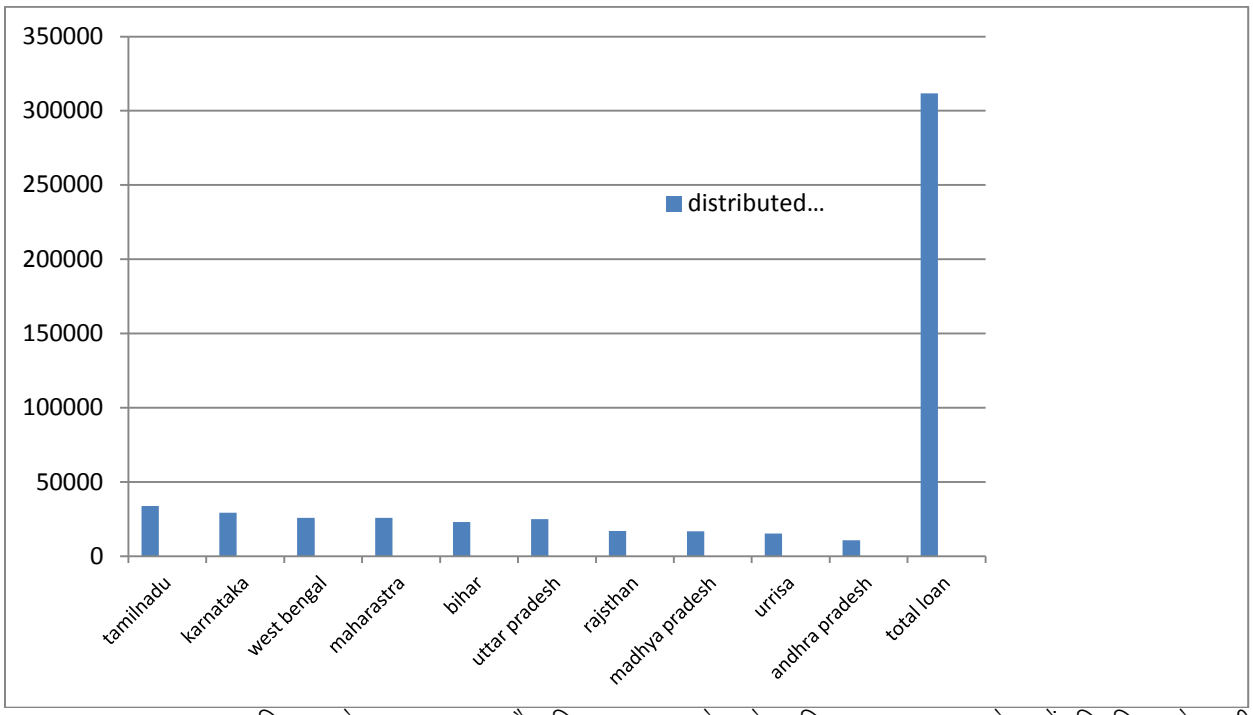

इस प्रकार तालिका से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक ऋण तमिलनाडु में 33,807.87 करोड़ रूपये वितरित किये गये जो कुल वितरित ऋण का 10.84 प्रतिशत सर्वाधिक था। वहीं कर्नाटक, पं0 बंगाल क्रमशः दूसरे व तीसरे नंबर पर है। वहीं सबसे अधिक बेरोजगारी वाले प्रदेश बिहार व उत्तर प्रदेश में वितरित लोन की हिस्सेदारी क्रमशः 7.39% तथा 7.98% है जो दक्षिणवर्ती राज्यों तमिलनाडु व कर्नाटक की तुलना में काफी कम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में विभिन्न संस्थाओं की मदद करती है जो इस प्रकार है–

बैंक	**करोड रूपया में कुल लोन**	**प्रतिशत हिस्सेदारी**
एस बी आई	33,612.5	10.78
सरकारी क्षेत्र के व्यावसायिक बैक	59,754.41	19.16
निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक	63,624.07	20.40
विदेशी बैंक	30.61	0.0098
राज्य सहकारी	1.6	0.00051
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	16,687.08	5.35
सुक्ष्म वित्तीय संस्थाएँ	23,57.41	0.756
NBFC सुक्ष्म वित्तीय संस्थाएँ	5,9115.7	1.89
नन बैंकिग वित्तीय संस्थाएँ	46,865.09	15.02
सुक्ष्म वित्त बैंक	29,762.92	9.54
कुल वितरित ऋण	3,11,811.38	100

(स्रोतः PMMY आर्थिक समीक्षा 2018–19)

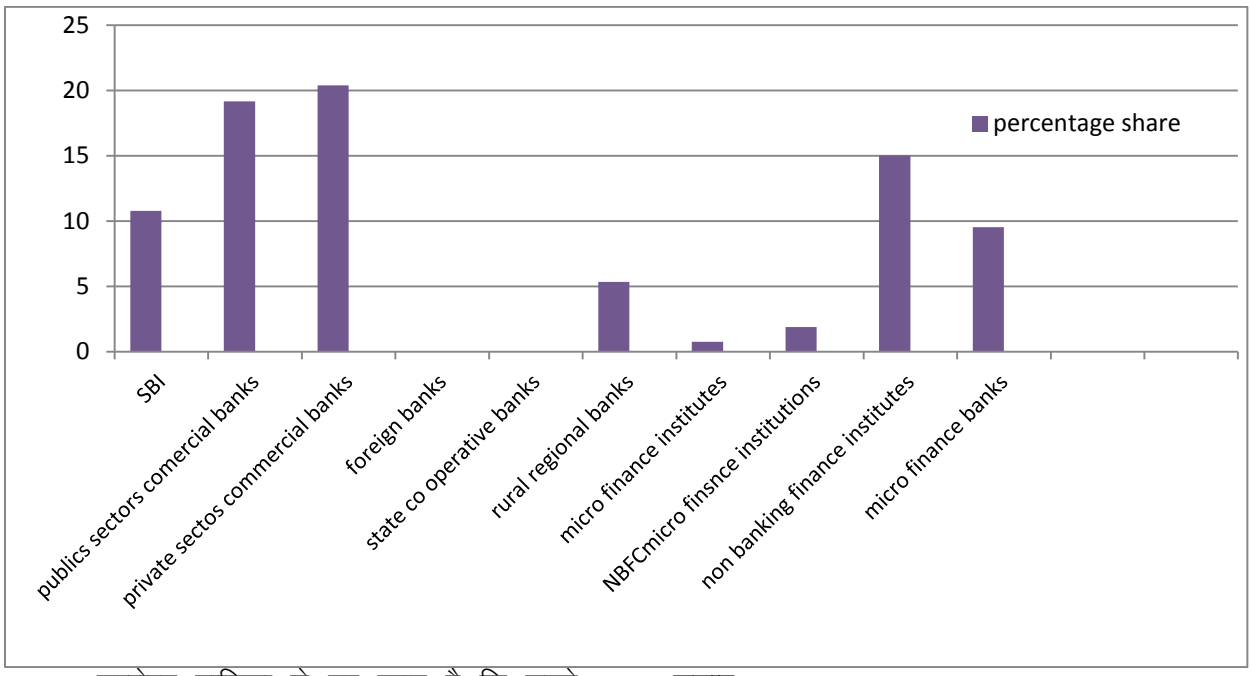

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक ऋण का वितरण इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंको की है। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंको की हिस्सेदारी 19.16 प्रतिशत है। वहीं एस0 बी0 आई0 व उसके सहयोगी बैंको की हिस्सेदारी 10.78 प्रतिशत है। वहीं व्यक्तिगत रूप से एस0 बी0 आई0 की ऋण वितरण में हिस्सेदारी सार्वाधिक है। वहीं नन वित्तीय संस्थाएँ 15 प्रतिशत है जो तीसरे स्थान पर है सबसे अधिक ऋण वितरित करने में राज्य सहकारी बैंक व विदेशी बैंक सबसे कम मुद्रा लोन वितरित किए है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समस्याएँ

1. इस योजना की वार्षिक ब्याज की दर 12 प्रतिशत है जो कि अधिक है।
2. इस योजना की दूसरी बड़ी समस्या इसकी उम्र सीमा 23–28 वर्ष है।
3. कारोबारी के लिए यह जरूरी है कि वह पिछले पांच वर्षों से कारोबार कर रहा हो
4. मुद्रा लोन के तहत नये उद्यमियों के लिए 50,000 तक ही उपलब्ध हैं। आज इतनी कम राशि में नया व्यापार शुरू करना काफी कठिन है।
5. निवास के लिए दिए गए प्रमाण–पत्र पर मुद्रा लोन लेने वाला आवेदक कम से कम एक साल से रह रहा हो।
6. यदि कोई उद्यमी मुद्रा लोन ले रहा हो तो उसके लिए यह जरूरी है कि उसका सालाना कारोबार 15 लाख रूपये हो।
7. मुद्रा लोन की जानकारी आम लोगों तक नहीं है।
8. कुछ बैंक इस योजना के अंतर्गत ऋण देने में कोताही करते है। ये सारी समस्याएँ इस योजना के साथ है।

सुझाव

1. इस योजना की लोन की ब्याज की दर को कम रखना चाहिए ताकि लोन नए कारोबारी के लिए बोझ ना बने।
2. इस योजना का लाभ सभी उम्र के उद्यमियों के लिए होने चाहिए ताकि रोजगार को बढावा मिले ।
3. शिशु लोन के अंतर्गत मिलने वाली राशि को इतना अवश्य बढाया जाना चाहिए कि एक नया व्यवसाय या उद्यम आरंभ किया जा सके।
4. निवास की सीमा को समाप्त करके देश के किसी भी कोने में भारतवासी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वह देश के किसी भी हिस्से में अपना व्यवसाय आरंभ कर सके।
5. यदि कोई उद्यमी लोन ले रहा है तो उसकी सालाना कारोबार की सीमा 15 लाख को समाप्त कर देना चाहिए ताकि उद्योग जगत में प्रतिस्पर्द्धा बढें। इस प्रकार इस योजना का उददेश्य तभी पूरा हो सकेगा जब इसकी कमियों को दूर करेंगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

www.mudra.org.in
www.niti.gov.in
www.ministrylabour.gov.in
www.the hindustantimes.com
www.the economictimes.com
The Hindustan Newspaper
The Prabhat Khabharnewspaper
The Yojna New Delhi (Monthly)
आर्थिक समीक्षा: आई एल0 ओ (ILO)
आर्थिक समीक्षा: भारत सरकार 2018–19
आर्थिक समीक्षा: मुद्रा योजना 2018–19